सिविल विविध।

. *माननीय न्यायमूर्ति ए.डी. कोशल के समक्ष*

किशन *लाल, - याचिकाकर्ता।*

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता।

**1970 की सिविल रिट संख्या 619।**

6 मई, 1970।

*पंजाब गौण खनिज रियायत नियम,* 1964 - *नियम* 28, 29, 30 (2) (आईओ), 32 *और 33* - नमक के दोहन के लिए नीलामी - सबसे ऊंची बोली लगाने वाला *हथौड़ा गिरने के बाद बोली का 50* प्रतिशत जमा करता है - सरकार न तो बोली की पुष्टि करती है और न ही अस्वीकार करती है - ऐसी बोली - "क्या स्वीकार किया जाना माना जाता है - वैध अनुबंध - क्या अस्तित्व में आता है।

अभिनिर्धारित किया कि पंजाब गौण खनिज रियायत नियम, 1964 के नियम 30 के उप-नियम (2) के खंड (iv) में शब्द "किसी भी बोली को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकार की पुष्टि नहीं की जाती है", स्पष्ट और स्पष्ट हैं और केवल एक अर्थ के प्रति अग्रसर हैं , अर्थात्, जब तक सरकार यह घोषणा नहीं करती कि उसने बोली स्वीकार कर ली है, बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा ताकि किसी भी पक्ष को कोई अधिकार न मिले। नियमों के अनुसार, पार्टियों के लिए बाध्यकारी अनुबंध तभी अस्तित्व में आएगा जब बोलीदाता विलेख निष्पादित करेगा या किसी भी मामले में बोली की स्वीकृति के बारे में सरकार द्वारा संचार से पहले नहीं। अत नमक के दोहन के लिए नीलामी में सरकार और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के बीच हथौड़ा गिरने और बोली का 50 प्रतिशत जमा करने पर वैध अनुबंध नहीं होता है। (पैरा 5)

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227* के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि 8 जनवरी, 1970* (अनुलग्नक 'बी') की *आक्षेपित अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्प्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जहां तक यह गांव हरनी खुर्द से संबंधित है और 12 फरवरी 1970 को फिर से नीलामी की घोषणा को शून्य और अवैध के रूप में घोषित किया जाए; याचिकाकर्ता के पक्ष में पिछली नीलामी की पुष्टि करना और प्रतिवादियों को सुख लाल, प्रतिवादी संख्या 10 के साथ समझौते को निष्पादित करने से रोकना।* 5.

एस.के. जैन, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

सुरिंदर सरूप, एडवोकेट, महान्यायवीद उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

ए. डी. कौशल न्यायमूर्ति –इ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227स याचिका को जन्म देने वाले तथ्य ये हैं। न्यायालय द्वारा जारी एक अधिसूचना (याचिका के अनुलग्नक 'ए') के अनुसरण में उद्योग निदेशक, हरियाणा, धाबवाली ब्लॉक में स्थित हरनी खुर्द गांव में नमक वाले क्षेत्रों की नीलामी 15 सितंबर, 1969 को की गई थी, जब याचिकाकर्ता, एक साल्टपेट्रे ठेकेदार, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला निकला, जिसकी बोली 12,500 रुपये तक थी। उन्होंने नियमों के अनुसार मौके पर ही 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया। प्रभावी होने के लिए, इस बोली को सरकार द्वारा नीलामी को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार पुष्टि की जानी थी। तथापि, वह स्थिति कभी नहीं पहुंची और 8 जनवरी, 1970 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में एक और अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसमें घोषणा की गई कि उपर्युक्त नमक वाले क्षेत्रों की नीलामी 12 फरवरी, 1970 को सुबह 1000 बजे की जाएगी। यह अधिसूचना हरियाणा के उद्योग निदेशक द्वारा भी जारी की गई थी, और संबंधित क्षेत्रों को नीलामी के लिए रखा गया था, जैसा कि इसमें घोषित किया गया था, सबसे अधिक बोली प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा 29,000 रुपये में दी गई थी।

(2) याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर इन क्षेत्रों की फिर से नीलामी को चुनौती दी है -

(1) जैसे ही उन्होंने 15 सितंबर, 1969 को सबसे ऊंची बोली लगाई, उनके और सरकार के बीच हरनी खुर्द में उपलब्ध नमक के दोहन के लिए 12,500 रुपये के भुगतान पर एक वैध अनुबंध शुरू हो गया और यह अनुबंध तब तक अच्छा रहेगा जब तक कि इसे सरकार द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। सरकार द्वारा किसी भी निरसन पर निर्णय नहीं लिया गया है या याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है, अनुबंध पूरे समय लागू रहा।

(2) सरकार द्वारा उचित समय के भीतर बोली की पुष्टि करने से इनकार नहीं किया गया है, बोली को पुष्टि माना जाना चाहिए।

(3) माल की बिक्री अधिनियम की धारा 64 के खंड (2) के प्रावधानों के मद्देनजर नीलामी में हथौड़ा गिरने के साथ ही याचिकाकर्ता के पक्ष में नमक की बिक्री प्रभावी हो गई।

(4) अधिसूचना (याचिका का अनुलग्नक 'बी') कानूनी रूप से अस्तित्वहीन थी, यह सरकार द्वारा पारित किसी भी आदेश के अनुसरण में नहीं की गई थी।

(5) अधिसूचना (ऐनी 'शूर' 'बी') को रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह कार्रवाई *दुर्भावनापूर्ण* तरीके से की गई है क्योंकि अकेले याचिकाकर्ता ने ऐसा किया है। एक ठेकेदार के रूप में चुना गया था जिसके मामले में फिर से नीलामी का आदेश दिया गया था।

(3) अत, वह प्रार्थना करते हैं कि अनुलग्नक ख में अधिसूचना और इसके अनुसरण में आयोजित नीलामी को रद्द किया जाए और 15 सितम्बर, 1969 को आयोजित नीलामी में उनके द्वारा लगाई गई बोली की पुष्टि की जाए।

(4) आधार (i) के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान नियम 28 और 29 के प्रावधानों, नियम 30 के उप-नियम (2) के खंड (iv) और (v) और पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) के खंड 32 और 33 (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) की ओर आकर्षित किया है, जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 15 के तहत बनाए गए हैं। 1957 के साथ-साथ नीलामी के निबंधन और शर्तों के पैराग्राफ 1 से 4 के लिए भी, जो अधिसूचनाओं का हिस्सा हैं, अनुपत्र 'ए' और 'बी' हैं। उन प्रावधानों और अनुच्छेदों को लाभ के साथ यहां पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:

"पंजाब लघु खनिज रियायत नियम

*  * *  $  $  *
# *  #  * *  *

*छ. - ठेकों का अनुदान।*

28. (1) सरकार द्वारा नीलामी या निविदा द्वारा अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान किए जा सकते हैं जिसके बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

(2) ठेकेदार द्वारा सरकार को प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण नीलामी में या निविदा द्वारा किया जाएगा जिसे ठेका प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) संविदा केवल ऐसे मामलों में प्रदान की जाएगी जो सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

29. पीठासीन अधिकारी बोलीदाताओं या निविदाकर्ताओं को कोई कारण बताए बिना किसी भी बोली या निविदा को अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है। जहां उच्चतम बोली या निविदा को अस्वीकार कर दिया जाता है, तथापि, इसका कारण सरकार को सूचित किया जाएगा।

30. (1) *  *  *  *  *

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

(4) जब तक सरकार द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तब तक किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीलामी पूरी होने पर परिणाम की घोषणा की जाएगी और अनंतिम चयनित बोलीदाता को अनुबंध के नियमों और शर्तों के उचित पालन के लिए बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरंत एक वर्ष के लिए और अन्य 25 प्रतिशत सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी;

(5) जिस व्यक्ति की बोली अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है, उसे छोड़कर सभी को नीलामी के पूरा होने पर अग्रिम राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। अग्रिम राशि को खंड (iv) के अधीन प्रतिभूति के साथ समायोजित किया जाएगा;

*  *  *  *  *

32. उन ठेकों के मामले में जहां वार्षिक राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं है, शेष राशि ठेकेदार द्वारा नीलामी या निविदा खोलने की तारीख पर जमा की जाएगी, जैसा भी मामला हो। अन्य मामलों में शेष राशि समझौते में निर्धारित नियत तिथियों पर अग्रिम में वार्षिक राशि की समान त्रैमासिक किस्तों में जमा की जाएगी।

33. जब बोली की पुष्टि की जाती है या निविदा स्वीकार की जाती है, तो बोलीदाता या निविदाकर्ता फॉर्म 'एल' में एक विलेख निष्पादित करेगा। विलेख का निष्पादन बोलीदाता या निविदाकर्ता को बोली या निविदा की स्वीकृति की सूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर किया

जाएगा और यदि उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है, तो बोली या निविदा को स्वीकार करने वाले आदेश को रद्द माना जाएगा और नियम 30 (2) (iv) या 31 (3) के तहत भुगतान की गई राशि, जैसा भी मामला हो, सरकार को जब्त कर लिया जाएगा:

परन्तु जहां सरकार या उसकी ओर से बोली या निविदा स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि बोलीदाता या निविदाकर्ता संविदा के निष्पादन में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं है, सरकार या अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ीन महीने की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद उचित समय के भीतर अनुबंध के निष्पादन की अनुमति दें।

नीलामी के नियम और शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को पीठासीन अधिकारी के पास 200 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी।

2. अनुबंध की अवधि 31 जुलाई, 1970 तक होगी।

3. नीलामी करने वाले खरीदारों को उन क्षेत्रों को छोड़कर उस गांव की राजस्व संपदा से नमक निकालने का अधिकार होगा, जिन्हें उद्योग निदेशक, हरियाणा द्वारा छूट दी जा सकती है।

4. जब तक सरकार द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तब तक किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीलामी पूरी होने पर परिणाम की घोषणा की जाएगी और अनंतिम चयनित बोलीदाता को वर्ष की बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमानत के रूप में और 25 प्रतिशत अग्रिम राशि के रूप में जमा करनी होगी।

5. इस संदेह के लिए उचित आधार के मामले में कि बोलीदाताओं द्वारा पूल बनाकर बोली को जानबूझकर कम रखा गया है, उद्योग निदेशक को बोली की उपेक्षा करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि नीलामी की तारीख के 30 दिनों की अवधि के भीतर पहले से दी गई बोली की दोगुनी राशि के बराबर एक और बोली की पेशकश की जाए।

6. (क) ठेकों के मामले में जहां रॉयल्टी की राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, नीलामी पूरी होने पर ठेकेदारों द्वारा पूरी राशि जमा की जाएगी।

(ख) अन्य मामलों में शेष राशि ठेकेदारों द्वारा निम्नानुसार जमा की जाएगी -

(1) इसके अलावा समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय बोली का 25 प्रतिशत।

(2) शेष 50 प्रतिशत बोली 1 मार्च से पहले या 1 मार्च को लगाई जाएगी। 1970.

(3) सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को अपनी पेशकश वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा और उसे सरकार के निर्णय का पालन करना होगा।

(4) जब बोलियों की पुष्टि हो जाती है, तो बोलीदाता को बोलियों की स्वीकृति की सूचना की तारीख से एक महीने के भीतर फॉर्म 'एल' में विलेख निष्पादित करना होगा। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसे कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किए जाते हैं, तो बोली को स्वीकार करने वाले आदेश को रद्द माना जाएगा और भुगतान की गई राशि सरकार को जब्त कर ली जाएगी:

बशर्ते कि उद्योग निदेशक विलेख के निष्पादन के लिए समय बढ़ा सकते हैं।

(5) इस सामग्री के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि एक बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी बोली की अनंतिम स्वीकृति के तुरंत बाद नमक जमा का दोहन शुरू कर दे और नियम 30 के उप-नियम (2) के खंड (iv) के साथ-साथ नीलामी के नियम और शर्तों के पैराग्राफ 4 से क्या तात्पर्य है कि जैसे ही उच्चतम बोलीदाता अपनी बोली की 50 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करता है। हथौड़ा गिरने के बाद, उसके और सरकार के बीच एक वैध अनुबंध अस्तित्व में आता है जो इस शर्त के अधीन है कि इसे उचित समय के भीतर सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, "जब तक सरकार द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा," शब्दों का अर्थ यह निर्धारित करने के रूप में लगाया जाना चाहिए कि उच्चतम बोली को सरकार द्वारा खारिज किए जाने तक स्वीकार किया जाएगा। यह व्याख्या उपरोक्त उप-नियम (2) और पैराग्राफ 4 के पत्र और भावना दोनों के मूल में है, जिसमें उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं और केवल एक

निर्माण के लिए अतिसंवेदनशील हैं, अर्थात्, जब तक सरकार यह घोषणा नहीं करती है कि उसने बोली स्वीकार कर ली है, तब तक बोली को स्वीकार नहीं माना जाएगा ताकि इसकी स्वीकृति तक किसी भी पक्ष को कोई अधिकार न मिले: नियमों और नियमों और शर्तों के अनुसार, पार्टियों के लिए बाध्यकारी एक अनुबंध केवल तभी अस्तित्व में आएगा जब बोलीदाता फॉर्म 'एल' में विलेख निष्पादित करेगा या, किसी भी मामले में, बोली की स्वीकृति के बारे में सरकार द्वारा संचार से पहले नहीं। इसलिए, आधार (i) पूरी तरह से निराधार है और इसे पीछे हटाया जाना चाहिए। 4. मैदान (ii) भी योग्यता रहित है। यह हो सकता है कि सरकार याचिकाकर्ता द्वारा दी गई बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में उचित समय के भीतर निर्णय लेने में विफल रही, लेकिन फिर यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने इस तरह बोली को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के रूप में मानने का अधिकार हासिल कर लिया। संभवतः उसे जो एकमात्र अधिकार प्राप्त हो सकता था, वह यह था कि वह उचित समय बीत जाने के बाद बोली पर टिके रहने से इनकार कर देता था, लेकिन नियमों और शर्तों में निहित स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

नीलामी की शर्तों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता था जब तक कि सरकार ने इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की हो।

(6) माल की बिक्री अधिनियम की धारा 64 के खंड (2) में कहा गया है:

"64. नीलामी द्वारा बिक्री के मामले में-

QJ * * * $ *

* * * * *

(2) बिक्री तब पूरी होती है जब नीलामीकर्ता हथौड़ा गिरने से या अन्य प्रथागत तरीके से इसके पूरा होने की घोषणा करता है; और, जब तक ऐसी घोषणा नहीं की जाती है, तब तक कोई भी बोलीदाता अपनी बोली वापस ले सकता है;

*_"

इस प्रावधान का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जो निश्चित रूप से नियमों और अधिनियम द्वारा शासित है जिसके तहत उन्हें बनाया गया था। अतः भूमि (iii) पदार्थ रहित है।

(7) आधार (iv) और (v) के संबंध में, यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता को *अनुबंध 'बी' में अधिसूचना और इसके अनुसरण में आयोजित नीलामी को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी बोली की सरकार द्वारा कभी पुष्टि नहीं की गई थी और परिणामस्वरूप उसने पहली नीलामी के तहत कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं किया था।*

(8) बताए गए कारणों के लिए, याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा